पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख–पत्र

वर्ष 16, अंक 3/2015

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित ग्राहक सुविधा केन्द्र का शुभारम्भ

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सहयोग से देश के पांच राज्यों में 'ग्राहक सुविधा' केन्द्रों की स्थापना की गई है। राजस्थान, गुजरात, बिहार, पश्चिमी बंगाल और कर्नाटक में स्थापित इन केन्द्रों में से राजस्थान में स्थापित केन्द्र के संचालन की जिम्मेदारी 'कट्स' को दी गई है। इस केन्द्र के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान आसानी से हो सकेगा।

यह जानकारी 'कट्स' निदेशक जॉर्ज चेरियन ने 15 सितम्बर को जयपुर में आयोजित केन्द्र के शुभारम्भ समारोह के दौरान दी। संस्था के वरिष्ठ कार्यक्रम समन्वयक दीपक सक्सेना द्वारा ग्राहक सुविधा केन्द्र के बारे में पॉवर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करते हुए विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस वी.एस. दवे ने अपने मुख्य सम्बोधन में कहा कि 'ग्राहक सुविधा केन्द्र' केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मंच के जरिए सभी हितधारी मिलकर उपभोक्ताओं की समस्याओं का निवारण करने के लिए कार्य करेंगे।

दवे ने सुझाव दिया कि आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यापारी वर्ग को भी ग्राहक सुविधा केन्द्र की कार्यप्रणाली के बारे में जागरूक करना होगा।

उपभोक्ता के हितों के लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए 'कट्स' के महामंत्री प्रदीप एस. महता ने बताया कि संस्था द्वारा बहुत से उपभोक्ताओं की शिकायतों को उपभोक्ता मंचों एवं न्यायालयों के माध्यम से पैरवी कर सुलझाया गया है।

महता ने कहा कि ग्राहक सुविधा केन्द्र में भी उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए सभी तरह के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

इस अवसर पर संजय झाला, उपनिदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान सरकार ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में स्वयंसेवी संस्थाओं, विभिन्न सेवा प्रदाताओं, नियामक एजेंसियों के प्रतिनिधियों व गणमान्य नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित

समारोह के दौरान जैविक खेती विषय पर उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए सुरेन्द्र कुमार सैनी 'चिराना' को प्रशस्ति पत्र एवं 10 हजार रुपए का चैक प्रदान कर 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 'कट्स' द्वारा वर्ष 2002 से हर साल उन पत्रकारों को दिये जाते हैं, जिन्होंने जनहित के मामलों को ग्रामीण पत्रकारिता के माध्यम से असरदार तरीके से उठाया है।

झुंझुनूं जिले के गांव देवीपुरा (नवलगढ़) निवासी चिराना ने वर्ष 2014 में जैविक खेती पर कई स्टोरियां प्रकाशित कर किसानों में जागरूकता लाने का प्रयास किया है। वह हिन्दी समाचार पत्र दैनिक भास्कर के सीकर संस्करण में एग्रीकल्चर रिपोर्टर हैं।

इस अंक में...

- सिकुड़ते जंगलों से करोड़ों का नुकसान 3
- अफसर बन गए बीपीएल 4
- थानेदार के लिए पत्नी ने ली रिश्वत 5
- टकराव का अखाड़ा बन गई संसद 7
- बोरिंग के पानी पर लगेगा चार्ज! 9

शहरी निकायों को सशक्त करने की आवश्यकता

शहरी निकायों को सशक्त किए बिना शहरों का विकास संभव नहीं है। निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शक्ति हस्तान्तरण भी जरूरी है। आम नागरिकों को शहरी निकायों में अपनी बात रखने के लिए किसी भी प्रकार का मंच उपलब्ध नहीं है। नागरिकों को वार्ड स्तरीय योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए ।

उक्त तथ्य 'कट्स' द्वारा संचालित 'माई सिटी' परियोजना के तहत 27 अगस्त को जयपुर में आयोजित एडवोकेसी बैठक में सामने आए। बैठक में भाग लेते हुए स्वायत शासन विभाग के निदेशक पुरषोत्तम बियानी ने निकायों के बेहतर संचालन में नागरिकों की भूमिका पर जोर देते हुए उन्हें अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों पर भी ध्यान देने की जरूरत जताई। संचिता विश्नोई, अतिरिक्त निदेशक स्वायत शासन विभाग ने कट्स के प्रयासों की सराहना करते हुए शहरों में नागरिक विकास समितियों के गठन की आवश्कता पर जोर दिया।

राजस्थान स्वायत शासन संस्था के निदेशक रामावतार रघुवंशी ने शहरी निकायों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने पर बल देते जयपुर निगम में आंतरिक सुधारों की जरूरत बताई। कार्यक्रम में विधायक मोहन लाल गुप्ता ने कहा कि नागरिकों को उपभोक्ता के रूप में मिलने वाली सेवाओं को प्राप्त करने का हक है। निगम अधिकारियों को समय पर सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए।

कार्यक्रम के प्रारंभ में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने स्थानीय निकायों को अधिक सशक्त करने की जरूरत बताते हुए इस बात पर जोर दिया कि 74वें संवैधानिक संशोधन की पालना करते हुए निकायों में नागरिकों को मंच उपलब्ध कराना चाहिए। 'कट्स' के परियोजना समन्वयक अमरदीप सिंह ने परियोजना की गतिविधियों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में जयपुर शहर के कई पार्षदों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास समितियों तथा मीडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

स्वायत शासन और स्थानीय निकायों में समन्वय की जरूरत

स्वायत शासन विभाग और स्थानीय शहरी निकायों के मध्य समन्वय की जरूरत है। इससे निकायों द्वारा समय पर एवं बेहतर कार्य किए जा सकेंगे। राज्य के सभी महापौरों को समय-समय पर एक मंच पर बुलाया जाना चाहिए ताकि उनसे सम्बन्धित समस्याओं का निवारण हो सके।

कोटा शहर के महापौर महेश विजय ने यह बात 'कट्स' द्वारा 22 सितम्बर को कोटा में माई सिटी परियोजना के तहत शहरी सुशासन पर आयोजित सम्मेलन में कही। उन्होंने इस अवसर पर कोटा नगर निगम की समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि निकायों का सशक्तिकरण कर अधिक कार्यकुशल बनाया जाना चाहिए। वहीं कोटा की उप महापौर सुनिता व्यास ने पार्षदों को जनता से जुड़ी सबसे मुख्य कड़ी बताते हुए उन्हें उपयुक्त शक्तियां देकर कार्यकुशल बनाये जाने की पैरवी की।

सम्मेलन में स्वायत शासन विभाग राजस्थान सरकार की अतिरिक्त निदेशक संचिता विश्नोई ने बताया कि निकायों को अधिक सशक्त व बेहतर बनाने के लिए विभाग स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। स्वायत शासन विभाग का 'कट्स' संस्था के साथ होने वाला एम.ओ.यू. इस क्षेत्र में मददगार साबित होगा और राजस्थान राज्य में महापौरों एवं उप महापौरों को आपसी चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराएगा।

'कट्स' निदेशक जॉर्ज चेरियन ने हाल ही जारी भारतीय शहरों की तालिका का जिक्र करते हुए बताया कि राजस्थान के सभी शहरी निकायों का काम काफी नीचे है। उन्होंने संविधान के 74वें संशोधन की जानकारी देते हुए कहा कि इसके अनुसार शहरी निकायों का सशक्तिकरण होना चाहिए। कार्यक्रम समन्वयक अमरदीप सिंह, ने महापौरों के इस सम्मेलन के उद्धेश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राजस्थान में महापौरों का यह विशेष मंच है जिसके जरिए चुनौतियों, समस्याओं व अनुभवों को आपस में बांटा जाता है।

पानी में हुए 500 करोड़ के घपले

जलदाय विभाग में पिछले पांच साल में इंजीनियरों ने मनमर्जी से टेंडरों में वित्तीय सीमा बढ़ा कर ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया। विभाग की ऑडिट रिपोर्ट में इस अनियमितता का खुलासा किया गया है। ऑडिट ने शिकायत पर जिस डिविजन में अनियमितता और वित्तीय सीमा बढ़ाने की जांच की, वहीं पर करोड़ों रुपए की गड़बड़ी सामने आई है।

पिछले पांच साल के टेंडर व वर्क ऑर्डर की गंभीरता से ऑडिट और जांच हो तो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी सामने आ सकती है। प्रकाश में यह भी आया है कि विभाग के इंजीनियर अपने चहेते ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर देने के लिए पहले कम एस्टिमेट पर टेंडर आमंत्रित करते हैं, बाद में वित्तीय सीमा बढ़ाने के लिए नोट बना कर अफसरों से पास करा लेते हैं, ताकि इससे अफसरों को भी ज्यादा कमीशन का भाग मिल सके।

(दै.भा., 05.07.15)

गॉज-बैंडेज जांच में फेल

सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल की जाने वाली गॉज-बैंडेज की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। औषधि नियंत्रण संगठन के ड्रग कन्ट्रोल ऑफीसर की ओर से राज्य के विविध जिलों से पिछले साल लिए गए गॉज-बैंडेज के 90 सैंपलों में से 70 फेल हो गए।

हाथकरघा उद्योग द्वारा निर्मित गॉज-बैंडेज के सैंपल हर बार फेल होने के बावजूद सरकार इन्हीं से खरीद करती है। गॉज-बैंडेज में सोखने की क्षमता नहीं होने पर संक्रमण का खतरा रहता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है। फॉर्मा एक्सपर्ट वी.एन.वर्मा के अनुसार गॉज-बैंडेज ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के शेड्यूल-2 में है। सरकार को क्वालिटी में सुधार के लिए निर्माता कंपनियों व उद्योगों का निरीक्षण कराकर विशेषज्ञों की देखरेख में निर्माण कराना चाहिए।

(दै.भा., 03.07.15)

नहीं मिला पालनहार योजना का लाभ

प्रदेश में अनाथ, बेसहारा, विधवा व परित्यक्ताओं के बच्चों को आर्थिक सहायता के लिए चलाई जा रही पालनहार योजना का लाभ सही रूप से नहीं मिल पा रहा। सरकार ने योजना का विभाग बदला और इसके बाद आवेदन का तरीका। प्रचार-प्रसार नहीं होने से जरूरतमंदों को योजना की जानकारी नहीं है।

जिन लोगों ने सालों पहले आवेदन किया था उन्हें अभी भी यह सहायता नहीं मिल रही। प्रदेश भर में 1.25 लाख बच्चे पालनहार है वहीं जयपुर में ही इनकी संख्या करीब 20 हजार है। इनमें से अधिकांश को सहायता राशि नहीं मिल रही, जबकि करीब सौ करोड़ से भी ज्यादा का बजट लैप्स हो गया।

(रा.प., 08.09.15)

आदर्श गांव योजना में नहीं ली रुचि

प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर प्रदेश में शुरू हुई मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना में प्रदेश के कई विधायक रुचि नहीं ले रहे हैं। इसमें मंत्री भी शामिल हैं। पांच मंत्रियों सहित 32 विधायकों ने अब तक आदर्श गांव के लिए गांव का चयन तक नहीं किया है। जबकि आखिरी तारीख को बीते दो माह गुजर चुके हैं। इन 32 विधायकों में 22 सत्ताधारी दल के हैं।

इस योजना के तहत हर विधायक को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श गांव का चयन करना है, जिसमें विधायक कोष का पैसा खर्च करने के साथ सरकार से अन्य मदों में वित्तीय राशि मंजूर कराकर गांव के विकास को आदर्श बनाने के काम करने हैं।

(दै.न., 02.09.15)

विधायक ने खोली मनरेगा की पोल

मनरेगा में भ्रष्टाचार व्याप्त है। कार्यस्थल पर श्रमिक नजर नहीं आते, जबकि फर्जी मस्टररोल में ऑनलाइन सिस्टम में श्रमिकों के नाम दर्ज हो रहे हैं। श्रमिकों के अनुपात में काम नजर नहीं आ रहा। जिले में बिना काम किए पैसे उठाने वाले लोगों का गिरोह बनता जा रहा है। इसमें ऑपरेटर से लेकर जेईएन तक सारा काम मिलीभगत से हो रहा है।

कोटा जिला परिषद् स्थित अटल सेवा केन्द्र में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान पीपल्दा के भाजपा विधायक विद्याशंकर नंदवाना ने पंचायतीराज मंत्री सुरेन्द्र गोयल को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा मनरेगा कार्यों का निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। कार्यस्थल व ऑनलाइन सिस्टम की जांच कराई जाए तो अपने आप हकीकत सामने आ जाएगी।

(रा.प., 01.08.15)

सिकुड़ते जंगलों से करोड़ों का नुकसान

सिकुड़ते जंगलों की वजह से राजस्थान को केन्द्रीय करों की हिस्सेदारी में से 0.4 फीसदी यानी करीब 1300 करोड़ रुपए का नुकसान भुगतना पड़ेगा। केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी तय करने के लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा हिस्सेदारी का फॉर्मूला बदलने से केन्द्रीय करों में हिस्सा घटा है। आयोग ने जंगलात क्षेत्र के लिए 7.5 फीसदी नंबर रखे हैं।

इससे पहले 13वें वित्त आयोग में जंगलात के नंबर शून्य थे। सौ नंबरों के फार्मूले में 1971 की जनसंख्या के आधार पर 17.5, 2011 की जनसंख्या के लिए 10, गरीब अमीर की खाई पाटने के लिए 50 एवं वित्तीय अनुशासन के लिए शून्य नंबर तय किए हैं।

(रा.प., 14.08.15)

जंगल हैं नहीं, पेड़ काटने में हम आगे

क्षेत्रफल के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान वन एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के उल्लंघन में सबसे आगे है। वनों की अवैध कटाई हो या जीवों के प्रति अपराध के मामले देशभर में सबसे ज्यादा राजस्थान में दर्ज है।

वर्ष 2013-14 के दौरान नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक राज्य में 2927 अपराध दर्ज हुए इनमें ज्यादातर मामले अवैध रूप से पेड़ काटने और वन सामग्री ले जाने के हैं। जबकि उत्तरप्रदेश में 1597 व कर्नाटक में 249 अपराध दर्ज हुए हैं।

(रा.प., 24.08.15)

अफसर बन गए बीपीएल

बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाने के लिए अच्छे पदों पर काम कर रहे, मोटी तनख्वाह पाने वाले सरकारी कर्मचारी और अफसर खुद को गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल बता रहे हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देने वाला समाज कल्याण विभाग भी इन विशेष 'बीपीएल' की जानकारी होने के बावजूद आंखें मूंदे बैठा है। सालाना छह लाख तक वेतन लेने वाले अधिकारी भी खुद को गरीब किसान बता कर अपने बच्चों के लिए स्कॉलरशिप ले रहे हैं।

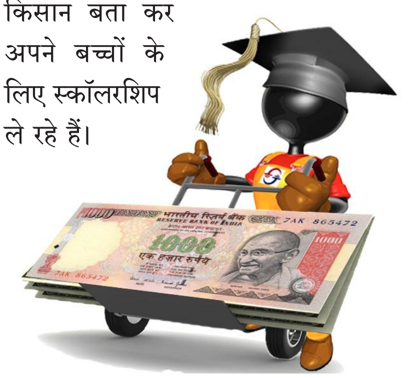

दैनिक भास्कर की ओर से की गई पड़ताल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें पूर्व मंत्री और विधायकों के बच्चों के नाम भी शामिल थे। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति के जरूरतमंद छात्रों को विभाग की ओर से स्कॉलरशिप दी जाती है। विभाग हर साल स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर के ऐसे छात्रों को स्कॉलरशिप देती है।

(दै.भा., 09.09.15)

ऐसे तो हो चुका गांवों का विकास

प्रदेश भर में ग्राम सेवकों के तीन हजार पद खाली पड़े हैं। प्रदेश में 9894 ग्राम पंचायतें हैं। जबकि इनमें 6500 ग्राम सेवक ही कार्यरत है, बाकी के पद खाली पड़े हैं। करीब 500 ग्राम सेवक ऐसे हैं, जिनके पास तीन से पांच पंचायतों तक का कार्यभार है, जिसे वे पूरा नहीं कर पाते।

अमूमन ग्राम पंचायत के सभी प्रशासनिक काम ग्राम सेवक को करने होते हैं। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुमति, पट्टा बनाना, इंदिरा आवास व मुख्यमंत्री आवास योजना के आवेदन तैयार कर भेजना, पेंशन योग्य ग्रामीणों के आवेदन तैयार करना, मनरेगा जॉब-कार्ड बनाना तथा स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय आदि के प्रस्ताव बनाकर भी ग्राम सेवक ही भेजता है। *(रा.-प., 03.08.15)*

करोड़ों का घपला, नहीं हुई वसूली

ग्रामीण विकास, पोषाहार, आवास और गरीबी उन्मूलन के लिए पिछले डेढ़ दशक में आए बजट में से साढ़े 41 करोड़ रुपए का घपला सामने आया है। इसमें ग्राम सेवक, सरपंच से लेकर बीडीओ, प्रधान, जिला परिषद के कार्मिक व अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इसके बावजूद जिला परिषद वसूली नहीं कर पाई और न ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो पाई है।

इस हेराफेरी का खुलासा प्रधान महालेखाकार द्वारा की गई ऑडिट रिपोर्ट से हुआ है। राजेन्द्र प्रसाद सारस्वत सीईओ, जिला परिषद, राजसमन्द का कहना है कि इस बारे में वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।

(रा.प., 02.09.15)

बच्चों के हक का खा रहे गुरूजी

बच्चों के पोषाहार के लिए आए मिड-डे-मील की खाद्य सामग्री व उनके पढ़ने के लिए आई पाठ्य पुस्तकों को गुप-चुप तरीके से बेचने जा रहे शिक्षक गोविन्द शर्मा को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वह करौली जिले के गांव मनाखुर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात हैं और बयाना उपखण्ड के गांव खरेरी के निवासी है।

उनके साथ टैम्पू चालक उनके चचेरे भाई पवन शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। इस टैम्पू में वह स्कूल के पोषाहार का गेहूं, चावल और पाठ्य पुस्तकें चुराकर चुपचाप बेचने जा रहे थे। ग्रामीणों व पुलिस का मानना है कि अक्सर स्कूलों से पोषाहार और पुस्तकों की चोरी के मामले दर्ज होते रहते हैं। कहीं उनके पीछे भी ऐसा ही खेल तो नहीं हो रहा? *(दै.न., 20.07.15)*

नई ग्राम पंचायतों का उधारी खाता

गांवों में विकास की रफ्तार तेज करने के मकसद से सरकार ने प्रदेश में 723 नई ग्राम पंचायतों का गठन तो कर दिया लेकिन ये ग्राम पंचायतें अपने खर्च भी उधार के भरोसे ही चला रही हैं। इन ग्राम पंचायतों का बैंक खाता पिछले सात माह से खाली है। इसके चलते इन ग्राम पंचायतों में विकास होना तो दूर सरपंच के मानदेय से लेकर वार्ड पंच का भत्ता तक उधारी में चल रहा है।

चुनाव से पहले गांव के विकास की बात करने वाले सरपंचों को जनता में जवाब देना भी भारी पड़ रहा है। इस बारे में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री सुरेन्द्र गोयल का कहना है कि फंड नहीं मिलने के कारण आवंटन नहीं हो पाया है। *(रा.प., 12.08.15)*

गटक गए पांच हजार 'टैंकर'

शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में टैंकरों से पेयजल आपूर्ति की आड़ में हुए लाखों रुपए के घोटाले में आखिर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने लम्बी प्राथमिक जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया है। कांग्रेस शासन के दौरान वर्ष 2013 में यह घोटाला सामने आया था। घोटाले में सत्रह लाख रुपए की गड़बड़ी का आरोप है।

दिलचस्प यह है कि यह घोटाला जलदाय विभाग के ही तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता वेद प्रकाश सैनी की शिकायत के बाद सामने आया था। अब वह ही खुद अन्य अधिकारियों के साथ इसमें फंस गए हैं। एसीबी ने जब जांच की तो वह भी इस घोटाले में लिप्त पाए गए। वर्तमान में सैनी दौसा जिले में कार्यरत है। *(दै.न., 03.09.15)*

प्रदेश में माइनिंग का मायाजाल

प्रदेश में माइनिंग का मायाजाल किसी तिलस्मी कहानी से कम नहीं है। बस कहानी के पात्र कुछ नेताओं, अफसरों व उनके रिश्तेदारों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। प्रदेश में 203 नेताओं और 45 अफसरों के परिजनों के पास 494 खानें हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार 25 मौजूदा व पूर्व मंत्री और 178 वर्तमान व पूर्व विधायकों के परिजन खानों के मालिक हैं। नेताओं व उनके रिश्तेदारों के पास 372 तथा अफसरों व उनके परिजनों के पास 122 खानें हैं।

भाजपा और कांग्रेस के अधिकांश नेता इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। प्रदेश में खुले आम खानों का यह खेल चल रहा है।

(दै.भा., 20.09.15)

घूस देने पहुंचे युवकों को पकड़वाया

काला बाजारी का गेहूं बेचने का मामला रफा-दफा कराने के लिए 50 हजार रुपए रिश्वत देने पहुंचे दो युवकों को एडीशनल डीसीपी कैलाश सांदू ने गिरफ्तार करा दिया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में इस प्रकार का रिवर्स मामला काफी समय बाद हुआ है। मामले के अनुसार आटे व गेहूं का कारोबारी जोधपुर के भवाद निवासी गंगाराम विश्नोई ट्रैक्टर ट्रॉली में राशन डीलरों से गेहूं लेकर बाजार में बेचने जा रहा था। करवड़ पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर गंगाराम को गिरफ्तार कर लिया।

इस पर गंगाराम के बेटे प्रेमाराम और भान्जे रणवीर ने कैलाश सांदू से फोन पर बात की और मामला रफा-दफा करने के लिए 50 हजार रुपए देने की पेशकश की। सांदू ने इसकी सूचना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दे दी। युवक जैसे ही रिश्वत की राशि कैलाश सांदू को देने लगे, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

(दै.भा. एवं रा.प., 05.07.15)

विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है भ्रष्टाचार

राज्य के लोकायुक्त एस.एस.कोठारी ने भ्रष्टाचार को देश के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा परिभाषित करते हुए कहा कि अगर राशि का उपयोग सही मायने में विकास योजनाओं की क्रियान्विति पर किया जाए तो यह समस्या समाप्त हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं।

उन्होंने कहा कि देश में शीर्ष से लेकर अर्श तक बैठे अधिकारी और कर्मचारी पद के दुरुपयोग के दलदल में धसते जा रहे हैं। ये इससे बाहर निकले तो ही देश विकास की मुख्य धारा से जुड़ पाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोकायुक्त को अधिक सशक्त करने के मकसद से तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन वह अभी तक अपनी रिपोर्ट तक नहीं दे सकी। *(दै.न., 16.09.15)*

दफ्तरों में भ्रष्टाचार रोकेंगी शिकायतें

प्रदेश के आम आदमी के लिए अच्छी सूचना है। जनता की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ की जाने वाली शिकायतें यूं ही डम्प नहीं पड़ी रहेगी। अब हर गुरुवार को जिला स्तर पर सरकार द्वारा कार्मिकों के खिलाफ की जाने वाली शिकायतों की समीक्षा की जाएगी।

इस सिलसिले में प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से नया दिशा-निर्देश जारी किया गया है। सरकारी हेल्प लाइन नंबरों पर जो शिकायतें की गई हैं, उनका क्या समाधान किया गया? इसके लिए प्रत्येक जिला कलेक्टरों की ओर से जन सुनवाई की जाएगी, जिसमें विधायक और जिला प्रमुख भाग लेंगे। इस दौरान शिकायत की समीक्षा की जाएगी।

(दै.भा., 31.08.15)

एसीबी भ्रष्टाचार का अखाड़ा

राजस्थान हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कार्यशैली पर तल्खी दिखाते हुए कहा है कि ब्यूरो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। अधिकारी अनुपयोगी है। इसे बन्द कर मामले सीबीआई को सौंप देने चाहिए। अदालत ने कहा कि ब्यूरो बड़े अफसरों पर तो हाथ डालता नहीं है और चपरासी व बाबू स्तर के कर्मचारियों को फंसा देता है।

न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह टिप्पणी फ्लाईंग ट्रेनिंग के तहत प्रमाण पत्र देने के मामले में ब्यूरो के विरोधाभास और रेलवे पुलिस के थानाधिकारी पर अदालती आदेश के बावजूद हाजिर नहीं होने के मामलों पर सुनवाई करते हुए की। जयपुर बैंच की इस लताड़ के बाद जोधपुर मुख्यपीठ ने भी जांच पर सवालिया निशान लगाते हुए एक मामले में एसीबी की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। *(रा.प., 03.09.15, 05.09.15)*

पकड़ने से पहले ही भाग रहे रिश्वतखोर

रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ने वाली भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) टीम के हाथ कमजोर पड़ने लगे हैं। कई मामलों में कार्रवाई की सूचना लीक होने से भ्रष्ट कार्मिक हाथ 'रंगने' से पहले ही भाग रहे हैं। सूचना की सेंधमारी से एसीबी महकमें में भी खलबली मची है।

इक्के-दुक्के मामलों को छोड़ दें तो एसीबी को कई मामलों की सूचना लीकेज करने वालों का अभी तक कोई मुख्य सुराग तक नहीं लग पाया है। अमूमन रूप से माना जाता है कि फरियादी, कार्रवाई करने वाली टीम और गवाह बनाए जाने वाले दो सरकारी कर्मचारियों को ही ट्रेप की जानकारी होती है। बावजूद इसके सूचना लीक करने वाले तक पहुंच नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। *(रा.प., 05.07.15)*

भ्रष्टाचार के मामलों में रियायत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार समाज को तेजी से प्रभावित कर रहा है। इसमें संलिप्त लोगों के साथ किसी भी तरह की रियायत नहीं की जा सकती। भ्रष्टाचारियों के कारनामों से ही यह कैंसर की तरह फैल रहा है। सभी अदालतें यह बात ध्यान में रखें।

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। उन्होंने भ्रष्टाचारी को ज्यादा सख्त सजा दिए जाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि ऐसे हालात में इसे नजर अन्दाज करना सही नहीं है। *(रा.प., 14.09.15)*

थानेदार के लिए पत्नी ने ली रिश्वत

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने थानेदार पति के लिए 70 हजार रुपए की रिश्वत ले रही पत्नी पारस कंवर व जोधपुर स्थित बिलाड़ा थाने में नियुक्त थानेदार परबत सिंह को गिरफ्तार किया है। प्रदेश में संभवतः यह पहला मामला है, जब पुलिस अफसर के साथ उसकी पत्नी भी घूस मामले में गिरफ्तार हुई है।

बिलाड़ा थाने में नियुक्त परबत सिंह ने जोधपुर के घोड़ों का चौक निवासी ज्वैलर ओमप्रकाश सोनी से बरामद 40 किलो चांदी को कोर्ट से दिलाने के लिए रिपोर्ट बनाने की एवज में यह राशि मांगी थी। थानेदार ने ओमप्रकाश से यह राशि जोधपुर में कुड़ी स्थित उनके घर पत्नी को देने के लिए कहा था। ओमप्रकाश की ओर से राशि देते ही एसीबी ने पारस कंवर को और बिलाड़ा थाने से उनके पति परबत सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

(दै.भा., 25.09.15)

पकड़ी गई घूस की खान

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए खान विभाग में 22 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत डील का भंडाफोड़ किया है।

उदयपुर और भीलवाड़ा में कार्रवाई को अंजाम देते हुए एसीबी ने रिश्वत के 4.28 करोड़ रुपए बरामद करने के साथ खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव अशोक सिंघवी और उदयपुर कार्यालय के अतिरिक्त निदेशक पंकज गहलोत समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

चित्तौड़गढ़ की 6 बंद खाने शुरू करने के एवज में कुल 22 करोड़ रुपए की डील थी। उदयपुर-भीलवाड़ा में बरामद 4.28 करोड़ रुपए पहली किश्त दी गई थी। मामले की जांच जारी है। *(रा.प., 17.09.15)*

भ्रष्ट पुलिस कर्मियों की होगी सूची तैयार

पुलिस की कार्यशैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित राजस्थान पुलिस जवाबदेही समिति की जन सुनवाई हुई तो उसमें फरियाद करने वालों का पूरे दिन तांता लगा रहा। पुलिस कमिश्नरेट का शायद ही कोई थाना बचा होगा जिसकी शिकायत नहीं हुई हो। ज्यादातर शिकायतें पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर थीं।

कमोबेश यही हाल जिला पुलिस से पीड़ित फरियादियों का था। आलम यह था कि समिति के चेयरमैन जस्टिस भंवरू खां ने लंच के लिए भी सुनवाई नहीं रोकी। अंत में उन्होंने कहा कि पुलिस के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश है। *(दै.भा., 22.08.15)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
जयपुर	प्रहलाद सिंह शेखावत	डिविजनल अकाउंटेंट, हसनपुरा जलदाय विभाग	50,000	*रा.प. एवं दै.भा., 07.07.15*
सीकर	मुकेश गुर्जर	जेईएन, अजमेर विद्युत निगम, अजमेर	10,000	*रा.प., 11.07.15*
जयपुर	चन्द्रमोहन पारीक बृजमोहन मीणा	फायर ऑफीसर, घाटगेट फायर स्टेशन, जयपुर फायरमैन, फायर स्टेशन, जयपुर	40,000	*रा.प. एवं दै.न., 14.07.15*
जयपुर	विशाल सिंघल	पटवारी, आमेर, जयपुर	8,000	*रा.प., 16.07.15*
जोधपुर	राम किशोर राठी	कार्यालय अधीक्षक, जोधपुर डिस्कॉम	7,000	*दै.न., 17.07.15*
सवाईमाधोपुर	सत्यनारायण नरूका	पटवारी, बौंली तहसील राजस्व हलका शीशोलाव	5,000	*दै.भा., 18.07.15*
अजमेर	श्रीपाल शेखावत	फोरमैन, खनिज विभाग, मकराना	3,50,000	*रा.प. एवं दै.भा., 24.07.15*
जयपुर	सुगड़ सिंह	कांस्टेबल, मोती डूंगरी थाना, जयपुर	10,000	*रा.प. एवं दै.न., 30.07.15*
उदयपुर	यशवीर सिंह	सहायक अभियंता, राष्ट्रीय बीज निगम, चित्तौड़गढ़	1,00,000	*रा.प., 02-.08.15*
भीलवाड़ा	नरेन्द्र सिंह राव	व.लिपिक, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग	7,000	*दै.भा., 05.08.15*
जयपुर	मनीष कुमार	फायरमैन, फायर स्टेशन, बगरू औद्योगिक क्षेत्र	5,000	*रा.प. एवं दै.न., 08.08.15*
चूरू	बैजूराम प्रजापत	हैड कांस्टेबल, सांड़वा थाना, चूरू	12,000	*रा.प. एवं दै.भा., 08.08.15*
जैसलमेर	पीताम्बर दास राठी	तहसीलदार, तहसील कार्यालय, जैसलमेर	4,000	*रा.प., 15.08.15*
जालौर	भंवरलाल माली देवेन्द्र आचार्य	चेयरमैन, नगर परिषद, जालौर दलाल	35,000	*दै.न. एवं दै.भा., 20.08.15*
हनुमानगढ़	गोविन्द सोनी	मैनेजर, केनरा बैंक, रावतसर	8,000	*दै.भा., 20.08.15*
अजमेर	बलवीर सिंह	सरपंच, रामनेर की ढ़ाणी, किशनगढ़	1,00,000	*रा.प. एवं दै.भा., 03.09.15*
अजमेर	जगदीश गोदारा	सहायक अभियंता, अजमेर कुचामन डिस्कॉम	15,000	*दै.भा. एवं रा.प., 03.09.15*
बाड़मेर	मुकेश सिंह	कनिष्ठ लिपिक, जिला उद्योग केन्द्र, बाड़मेर	10,000	*रा.प. एवं दै.भा., 03.09.15*
श्रीगंगानगर	प्रीतमलाल अरोड़ा	सहायक कर्मचारी, जलदाय विभाग	5,000	*रा.प., 03.09.15*
जयपुर	हरि किशन	सहायक उप निरीक्षक, चौंमू थाना, जयपुर	1,90,000	*दै.भा. एवं दै.न., 15.09.15*
बारां	सीमा यादव	पटवारी, बटावदी हल्का, अंता	5,000	*दै.भा., 15.09.15*
बीकानेर	लालचंद सोनी आशिक	कनिष्ठ लेखाकार, नगर विकास न्यास, बीकानेर सहयोगी, लालचंद सोनी	60,000	*दै.भा., 19.09.15*

टकराव का अखाड़ा बन गई संसद

संसद का पूरा मानसून सत्र हंगामें की भेंट चढ़ गया। इस पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि संसद परिचर्चा की बजाय टकराव के अखाड़े में बदल गई है। राजनीतिक दलों और जनता को इस पर गंभीर चिंतन कर कोई उपाय ढूंढ़ना होगा।

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हमारी संस्थाएं दबाव में हैं। हमारा लोकतंत्र रचनात्मक है, क्योंकि यह बहुलवादी है, परन्तु इस विविधता का पोषण सहिष्णुता और धैर्य के साथ किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त उर्वर भूमि पर, भारत जीवंत लोकतंत्र के रूप में विकसित हुआ है। इसकी जड़ें गहरीं हैं, परंतु पत्तियां मुरझाने लगी हैं। अब इनमें नवीनता लाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों व जनता के लिए इस पर गंभीर चिंतन करने का वक्त आ गया है, ताकि सुधारात्मक उपाय अंदर से आ सकें। *(रा.प., दै.न., 15.08.15)*

'सबके लिए घर' योजना को मंजूरी

केन्द्र सरकार ने 'सबके लिए घर' योजना के तहत पहले चरण में नौ राज्यों के 305 शहरों को चुना है। योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए 2022 तक दो करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है। गरीबों को घर खरीदने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से 1 से 2.3 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी।

इस योजना में राजस्थान के जयपुर, अजमेर, जोधपुर व उदयपुर सहित 40 शहर शामिल हैं। केन्द्र ने योजना की पहली किश्त के रूप में राज्य को 139.50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। दिल्ली में आयोजित मीटिंग में राज्य सरकार की सहमति पर यह राशि स्वीकृत की गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2022 तक सभी को छत उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की थी।

(दै.भा., 20.08.15, 31.08.15)

बच्चों से सीखिए डिजिटल ताकत

विकास के सपने दिखाने वाली डिजिटल इंडिया योजना की शुरूआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार इस पर एक लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने दावा किया है कि यह हमारी जिन्दगी को आसान बना देगी। इससे पारदर्शी गवर्नेंस में मदद मिलेगी। हम अब ई-गवर्नेंस से एम-गवर्नेंस की ओर मतलब मोबाइल गवर्नेंस की ओर आएंगे। पूरी सरकार आपके मोबाइल पर होगी।

उन्होंने कहा वक्त बदल रहा है पहले बच्चा आपका पैन खींचता था, चश्मा खींचता था। अब वह मोबाइल छीनता है। बच्चा कुछ समझे न समझे, लेकिन डिजिटल ताकत को समझता है। हम भी इस बदलाव को समझें, अगर नहीं समझेंगे तो देखते रह जाएंगे और दुनिया कहीं दूर निकल जाएगी। उन्होंने भारतीय युवाओं को तैयार रहने का आह्वान किया।

(दै.भा., 02.07.15)

प्रदेश में फिर सूखे के हालात

सामान्य से कम बरसात होने के कारण पांच साल बाद राज्य के लगभग आधे जिलों में सूखे के हालात बनते नजर आ रहे हैं। बरसात की कमी की वजह से रबी की फसल पर भी संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश के किसान काफी परेशानी में है। पहले बेमौसम बरसात और ओलों की मार ने फसल चौपट की है तो अब बरसात कम होने से तो अन्नदाता की कमर ही टूट गई है। जरूरत किसानों को जल्द ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाने की है।

राज्य सरकार ने 35 फीसदी तक फसल खराबे की बात स्वीकार की है, लेकिन गिरदावरी रिपोर्ट आने पर वास्तविक स्थिति सामने आएगी। सतही जल नहीं होने से आगे पैदावार में कमी आएगी जिससे महंगाई और भी मुंह फाड़ेगी। हालांकि केन्द्र व राज्य सरकार ने किसानों को पूरी मदद का आश्वासन जरूर दिया है। *(रा.प.,27.09.15)*

हर ग्रामीण के पास होगा 'रुपे कार्ड'

शहरी लोगों की जेब में रहने वाले क्रेडिट कार्ड की तरह अब ग्रामीणों के हाथ में भी 'रुपे कार्ड' होगा। इससे न केवल नगदी निकाली जा सकेगी, बल्कि खरीददारी भी हो सकेगी।

राज्य सरकार फिलहाल यह योजना आंशिक रूप से शुरू कर रही है। इसके तहत एक साल में प्रदेश के एक करोड़ 30 लाख बैंक खातों को सहकारी बैंकों के माध्यम से रुपे कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसके बाद केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का पैसा इन बैंकों के खातों में ही जमा होगा।

(रा.प., 22.08.15)

जैविक खेती पर पुरस्कार

राज्य सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहली बार तीन किसानों को एक-एक लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान करेगी। कृषि विभाग ने किसानों से 15 अक्टूबर, 2015 तक आवेदन मांगे हैं। जो भी किसान जैविक खेती अपना रहे हैं वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

किसानों को खेती में अपनाई गई नई तकनीक और प्रयोगों के बारे में पांच साल की जानकारी देनी होगी। *(रा.प., 07.09.15)*

अंगूठे की छाप से मिलेगा राशन

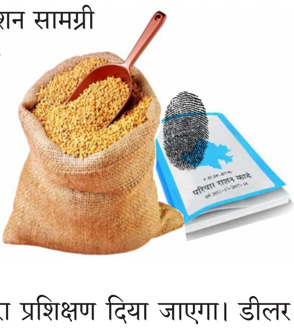

प्रदेश की सभी राशन दुकानों पर अब अंगूठे की छाप से राशन सामग्री मिलेगी। इसके लिए दुकानों पर तीन चरणों में पोश मशीन लगाई जाएंगी। पोश मशीन से खाद्य सामग्री का वितरण करने के लिए राशन कार्ड की ऑनलाइन फीडिंग शुरू हो गई है। राशन डीलर मशीन में हर उपभोक्ता के अंगूठे की निशानी स्केन करेंगे। मशीन से दिए गए सामान की रसीद भी मिलेगी।

दुकान से होने वाले वितरण की पल-पल की रिपोर्ट विभाग के पास अपडेट होगी। इसके लिए राशन डीलर को पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा। डीलर के कमीशन में बढ़ोतरी भी की जाएगी। इससे राशन दुकानों की आए दिन होने वाली कालाबाजारी की शिकायतों पर अंकुश लग सकेगा। *(रा.प., 24.07.15)*

हाईवोल्टेज से नुकसान पर हर्जाना

बिजली कनेक्शन मे देरी हो या निर्धारित समय से अधिक बिजली कटौति या फिर हाईवोल्टेज से उपकरण जलने पर उपभोक्ताओं को हर्जाना मिलता है।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने व ऐसा नहीं करने पर बिजली कंपनियों पर हर्जाना तय करते हुए स्टेण्डर्ड ऑफ परफोर्मेंस के नियम बनाए हैं। लेकिन बिजली कंपनियों की सेवाओं से नाखुश रहने के बावजूद उपभोक्ता सेवा दोष की स्थिति में मिलने वाले हर्जाने के अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे। हालात यह है कि स्टेण्डर्ड ऑफ परफोर्मेंस लागू हुए 10 महीने बीत चुके हैं, फिर भी महज गिने चुने लोग ही सेवा दोष का हर्जाना मांगने के लिए आगे आए हैं। *(रा.प., 20.08.15)*

नियंत्रण के लिए बना ऊर्जा निगम

राज्य में बिजली कंपनियों पर नियंत्रण के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम का गठन किया गया है। इसके हाथ में पांचों बिजली कंपनियों की कमान होगी। यह कम्पनी पूरी तरह सरकारी होगी। पांचों बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशक इसके डायरेक्टर होंगे तथा विद्युत विभाग के प्रमुख शासन सचिव इसके चेयरमैन होंगे।

संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में हुई केबिनेट की बैठक के बाद यह जानकारी देते हुए बताया कि नई कंपनी मुख्यतःबिजली की अल्पकालीन व दीर्घकालीन खरीद के अलावा वितरण निगमों के नियामक का कार्य और विद्युत उत्पादन प्रसारण एवं वितरण निगमों में समन्वयन का काम करेगी।

(रा.प. एवं दै.भा., 26.08.15)

पूरा करें अक्षय ऊर्जा का बैकलॉग

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देते हुए रिन्यूएबल एनर्जी पर्चेज ऑब्लिगेशन (आरपीओ) के मापदण्डों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब 2007 से आरपीओ मापदण्ड पूरा कराने के लिए अक्षय ऊर्जा निगम को जिम्मा दिया गया है।

प्रदेश में बाहर से सस्ती बिजली का जुगाड़ करने या खुद बिजली पैदा कर उपयोग करने वाले उद्यमियों को अक्षय ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) से दूरी बनाना अब महंगा पड़ेगा। ऐसे उद्यमियों को न सिर्फ निर्धारित मापदण्डों के मुताबिक ग्रीन एनर्जी के अपने बैकलॉग को पूरा करना होगा बल्कि आगे भी इसकी पालना करनी होगी। बैकलॉग पूरा नहीं करने पर प्रति यूनिट 3.59 रुपए के हिसाब से राशि वसूली जाएगी।

(रा.प., 12.09.15)

रिमोट से एक करोड़ की बिजली चोरी

जयपुर डिस्कॉम के दस्ते ने झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में रिमोट से मीटर को धीरे चला कर बिजली चोरी कर रही श्री श्याम आइस फैक्ट्री पर कार्रवाई की। फैक्ट्री में इस तरीके से अब तक एक करोड़ रुपए की बिजली चोरी की जा चुकी है। राजधानी की यह अब तक की सबसे बड़ी बिजली चोरी है।

फैक्ट्री में बिजली मीटर से ठीक पहले लगे टेस्ट टर्मिनल बॉक्स की आड़ में रिमोट से संचालित सर्किट लगा कर मीटर की गति धीमी की गई थी। मामले में किसी गिरोह की सक्रियता अथवा फील्ड स्टाफ की मिलीभगत होने की आंशका जताई जा रही है। फैक्ट्री मालिक को एक करोड़ रुपए जमा कराने का नोटिस दिया गया है साथ ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। *(रा.प., 14.08.15)*

सरकार सिर्फ 44 रुपए में देगी एलईडी

सरकार आम लोगों को सिर्फ 44 रुपए में एलईडी बल्ब देने पर विचार कर रही है। बाजार में इसकी मौजूदा कीमत 275 से 300 रुपए है। सरकार के इस कदम का मकसद अधिक बिजली खर्च करने वाले परम्परागत बल्बों के इस्तेमाल को कम करना है।

बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी एक कार्यक्रम में देते हुए कहा कि सरकार प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए बड़ी मात्रा में एलईडी बल्ब खरीदेगी। फिर उन्हें 44 रुपए में लोगों को उपलब्ध कराएगी। सरकार ने अभी तक करीब 1.35 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए हैं। तीन साल में बल्क ऑर्डर के जरिए खरीद कर 70 करोड़ बल्ब वितरित करने का लक्ष्य है। इससे करीब 25 अरब यूनिट बिजली की बचत हो सकेगी। *(दै.भा., 14.09.15)*

महंगी होगी बिजली, याचिका दायर

प्रदेश में राज्य सरकार ने बिजली की दरों में 6 से 12 फीसदी इजाफा करने का मन बना लिया है। राज्य की बिजली कंपनियों पर 30 बैंकों का करीब 80 हजार करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ऋण चुकाने में रियायत के लिए रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन से बात की थी, लेकिन उन्होंने रियायत देने में असमर्थता जाहिर करते हुए दरें बढ़ाने का सुझाव दिया।

15 साल पहले 2 हजार 300 करोड़ रुपए के घाटे को पाटने के लिए सरकार ने राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (आरएसईबी) को भंग कर बिजली की पांच कंपनियां बनाई थी। आज इन कंपनियों का घाटा बढ़ कर 90 हजार करोड़ रुपए को पार कर गया है। इसके साथ ही डिस्कॉम ने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में याचिका दायर कर 10 से 12 फीसदी तक बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया हुआ है। *(रा.प., 26.08.15 एवं दै.भा., 01.09.15)*

अक्षय ऊर्जा को प्रतिबद्ध सरकार

बिजली, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 2022 तक 1.75 लाख मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसमें एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा होगी। सरकार इस लक्ष्य को मिशन के रूप में पूरा कर रही है।

गोयल ने विज्ञान भवन में केन्द्र व राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान यह प्रतिबद्धता जाहिर की थी। *(न.ज़ु., 08.07.15)*

बोरिंग के पानी पर लगेगा चार्ज!

अगर आप घर के बोरिंग को खुद की संपत्ति मानकर धड़ल्ले से पानी का दोहन कर रहे हैं तो अब संभल जाइए। यह काम आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है और साथ ही इस पानी पर आस-पास के कई लोग भी हकदार हो जाएंगे। भूजल स्तर गिरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हुई सुनवाई के बाद देशभर में वैध-अवैध बोरवेल पर मीटर लगाने का मामला उठा है।

कोर्ट ने केन्द्र सरकार से जवाब तलब किया है कि क्यों नहीं बोरिंग के जरिए निकाले जा रहे भूगर्भ के पानी को कानून के दायरे में लाया जाए। मद्देनजर केन्द्र सरकार ने अपने स्तर पर बोरिंग पर मीटरिंग करने और इस पानी पर शुल्क वसूलने पर विचार करना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों की माने तो इस तरह की कवायद से भूजल स्तर में आ रही गिरावट पर काफी हद तक लगाम कसी जा सकेगी। *(रा.प., 05.08.15)*

जल संरक्षण में राजस्थान अव्वल

प्रदेश ने पानी बचाने के मामले में देश के दूसरे राज्यों को पछाड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है। केन्द्रीय भूमि संसाधन विभाग द्वारा हाल ही जारी 2014-15 की रिपोर्ट में बताया गया है कि राजस्थान ने 32 हजार 158 वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर शेड स्ट्रक्चर बनाकर देश में पहला स्थान बनाया है। प्रदेश ने देश में सर्वाधिक 11 हजार 460 चेक डेम बनाए।

रिपोर्ट के अनुसार 32 हजार से ज्यादा पानी बचाने और संरक्षित करने के स्ट्रक्चर बनाकर न केवल भू-गर्भ में सर्वाधिक पानी संरक्षित किया, बल्कि सूखे क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने की दिशा में भी अच्छा काम किया है। प्रदेश में यह काम जल संसाधन विभाग, संबंधित विभागों की तरफ से तथा जन सहभागिता से करवाए गए। *(दै.भा., 05.08.15)*

गांवों में चलेगा जल ग्रहण अभियान

राजस्थान में जल की अत्यधिक कमी और भू-जल स्तर में लगातार गिरावट हो रही है। इससे अकाल की संभावना दिखाई दे रही है। मद्देनजर राज्य सरकार ने 13 दिसम्बर से जन समुदाय व विभिन्न विभागों के समन्वय से मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत 4 वर्षों में 21 हजार गांवों में जल ग्रहण क्षेत्र विकास के कार्य कराए जाएंगे।

प्रथम चरण में 3 हजार गांवों का चयन कर जून, 2016 तक इस कार्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके बाद हर साल 6-6 हजार गांवों में यह कार्य होगा। इस अभियान में जल ग्रहण ढांचों की मरम्मत, नालों से मिट्टी निकालना व गहरा करना तथा कुओं तथा नलकूपों का जल स्तर बढ़ाने सहित कई कार्य कराए जाएंगे।

(दै.न., 20.09.15, 30.09.15)

सरस्वती नदी खोज पर केन्द्र की मुहर

राजस्थान में वैदिक काल में बहने वाली सरस्वती नदी की खोज पर अब केन्द्र सरकार ने भी मुहर लगा दी है। केन्द्र ने नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 68 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जलदाय विभाग की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्री उमा भारती ने सरस्वती नदी व सहायक नदियों के पुरामार्ग के पुनर्जीवीकरण के अन्वेषण एवं अनुसंधान के लिए बजट राशि स्वीकृत की थी।

प्रदेश की जल संसाधन मंत्री किरण माहेश्वरी ने बताया कि सरस्वती नदी पुनर्जीविकरण परियोजना से स्थानीय जिलों को स्वच्छ पेयजल मिल सकेगा।

(रा.प., 30.07.15)

ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 124 करोड़

जलदाय विभाग द्वारा आठ जिलों की ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए 124 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी गई है। जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हनुमानगढ़ को 74 करोड़, श्रीगंगानगर को 70 करोड़, बीकानेर को 25 करोड़, डूंगरपुर को 3 करोड़, बांसवाड़ा को 12.50 करोड़, अजमेर को 2.59 करोड़, चित्तौड़गढ़ को 2.36 करोड़ व उदयपुर को 8.50 करोड़ रुपए की राशि दी गई है ।

उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल मिले यह सरकार का महत्वपूर्ण मिशन है।

(दै.न., 13.07.15)

बदलेंगे पानी के खराब मीटर

राजस्व की भरपाई करने के लिए पानी के खराब मीटरों को बदला जाएगा। मीटर बदलने पर होने वाले खर्च की वसूली उपभोक्ताओं से ही होगी। यह राशि एक निश्चित किश्त के तौर पर वसूली जाएगी खराब मीटर बदलने के लिए पहले नीति का मसौदा तैयार किया जाएगा।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री किरण माहेश्वरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। माहेश्वरी ने बताया कि पेयजल से संबंधित घरेलू, व्यावसायिक एवं औद्योगिक पानी के मीटरों को बदलने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को नीति बनाकर अमल में लाया जाएगा।

(दै.न., 22.09.15)

जल संरक्षण हेतु चले आंदोलन

प्रदेश का दो तिहाई हिस्सा डार्क जोन में है। इस संकट से बाहर निकलने के लिए यहां भी जल संरक्षण को लेकर महाराष्ट्र की तरह जन आंदोलन चलाए जाने की जरूरत है। इसमें विधायक से लेकर हर जनप्रतिनिधि को अपनी भागीदारी निभानी है। जिला कलेक्टरों को भी महाराष्ट्र के अधिकारियों की तरह जोश और जुनून दिखाना है।

यह बात मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जल संरक्षण एवं मृदा संरक्षण आमुखीकरण कार्यशाला में कही। कार्यशाला में महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्र में चल रही जलयुक्त सिवाड़ अभियान का यहां के अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण किया। राजे ने बताया कि राजस्थान में भी जन सहभागिता की इस योजना को लागू करने की तैयारी चल रही है। *(रा.प., 25.07.15)*

महिला समानता से बढ़ेगा जीडीपी

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का कहना है कि रोजगार में महिलाओं को समानता देकर भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 27 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकता है। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टिन लगार्ड ने अंकारा में महिला सशक्तिकरण पर आयोजित जी-20 देशों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन के दौरान उक्त विचार व्यक्त करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण से आर्थिक विकास को भी गति मिलती है।

सुश्री लगार्ड ने कहा कि सुरक्षित और अच्छी आमदनी वाले रोजगारों में महिलाओं की संख्या बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी होगी। खाद्य एवं कृषि संगठन के एक अध्ययन का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि यह गरीबी कम करने में सहायक होगा।

(दै.न., 08.09.15)

जच्चा-बच्चा के लिए 'कुशल मंगल'

प्रदेश में अब जच्चा और बच्चा कुशल मंगल होंगे। इसके लिए 'कुशल-मंगल' कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। विश्व जनसंख्या दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने यह जानकारी देते हुए कहा कि अति जोखिम वाले प्रसव की स्थिति में यह कार्यक्रम मातृ मृत्यु दर रोकने में कारगर होगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों के मुताबिक राज्य में हर साल करीब 19 लाख 60 हजार महिलाएं गर्भधारण करती हैं। इनमें से करीब एक लाख 90 हजार महिलाएं अति जोखिम की स्थिति से गुजरती है। गर्भवती की एएनसी जांच के बाद फोन कर पूछा जाएगा कि उसे किसी तरह की समस्या तो नहीं है। किसी तरह की समस्या होने पर एएनएम उसके पास पहुंचकर तत्काल सभी चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

(रा.प. एवं दै.भा., 12.07.15)

अपराध में प्रदेश तीसरे पायदान पर

महिलाओं संबंधी अपराध के सर्वाधिक 38467 मामले उत्तरप्रदेश के है, जबकि 38299 मामले पश्चिम बंगाल के हैं। राजस्थान 31151 मामलों के साथ तीसरे पायदान पर है। पिछले साल प्रदेश देश में चौथे स्थान पर था, लेकिन अपराधों में बढ़ोतरी होने से राज्य एक पायदान और चढ़ गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से जारी वर्ष 2014 के आकड़ों में यह खुलासा हुआ है।

रिपोर्ट से यह भी सामने आया है कि महिलाओं से दुष्कर्म में मध्यप्रदेश सर्वाधिक 5076 मामलों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि राजस्थान दुष्कर्म के 3759 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश दुष्कर्म के 3467 मामलों के साथ तीसरे नम्बर पर है। जयपुर, जोधपुर व कोटा दुष्कर्म के मामलों में 53 शहरों की सूची में टॉप टेन में शामिल है।

(रा.प., 31.08.15)

जयपुर में खुला महिला सहायता केन्द्र

पीड़ित और शोषित महिलाओं को हर प्रकार की मदद तत्काल देने के मकसद से जयपुर स्थित जयपुरिया अस्पताल में 'अपराजिता' केन्द्र की दो साल पहले स्थापना की गई थी। इस अवधि में केन्द्र पर अपनों की सताई अर्थात घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं सबसे ज्यादा तादाद में पहुंची है।

केन्द्र पर 24 घंटे परामर्श, चिकित्सा, विधिक परामर्श और पुलिस आश्रय जैसी सुविधाएं तत्काल मुहैया कराई जाती है। पिछले दो साल में 1427 महिलाओं को न्याय दिलाया जा चुका है। जानकारी के अभाव में कम ही महिलाएं केन्द्र तक पहुंच रही हैं।

छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, बलात्कार एवं पीड़ित महिलाएं 0141-2553763, 2553764 पर कॉल कर सहायता ले सकती हैं। *(रा.प. 31.08.15 एवं दै.भा., 28.09.15)*

बालिकाओं के नाम होगी एफडी

आठवीं कक्षा उत्तीर्ण कर नवीं में पढ़ने वाली छात्राओं को अब तीन हजार रुपए की एफडी मिलेगी और दो साल बाद मय ब्याज सहित यह राशि दी जाएगी।

केन्द्र सरकार माध्यमिक शिक्षा के तहत बालिकाओं के प्रोत्साहन को लेकर राष्ट्रीय योजना के तहत सत्र 2015-16 के प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से छात्रवृत्ति पोर्टल तैयार करवा रही है। इसके बाद बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय योजना के तहत राज्य सरकार एफडी के रूप में यह छात्रवृत्ति शुरू करेगी। *(दै.भा., 05.07.15)*

राज्य में लागू है पीड़ित प्रतिकर योजना

समाज के कमजोर तबके और विभिन्न हादसों या वारदात के शिकार होने वाले महिला व बच्चों को आर्थिक सहायता के लिए प्रदेश में पीड़ित प्रतिकर योजना तो लागू है, लेकिन इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सतीश शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि महिला एवं बच्चों से दुष्कर्म और यौन हिंसा की वारदात घटित होने पर पीड़ित को राज्य सरकार की ओर से पांच लाख रुपए की सहायता व इलाज के लिए 25 हजार रुपए तक मिल सकते हैं। प्राधिकरण इस योजना के बारे में सेमिनार आयोजित कर लोगों को जागरूक कर रहा है। *(रा.प., 14.08.15)*

'आधी आबादी' का सुरक्षा कवच होगा मजबूत

प्रदेश के सात जिलों में आधी आबादी यानी महिलाओं की सुरक्षा का कवच और सशक्त होगा। केन्द्र सरकार की पहल पर राज्य में इन्वेस्टीगेशन यूनिट ऑफ क्राइम अंगेस्ट वुमैन (आईयूसीडब्ल्यू) खोलने के लिए सात जिलों अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, पाली, झालावाड़, श्रीगंगानगर और उदयपुर जिलों का यूनिट खोलने के लिए चयन हो गया है।

इन जिलों में पीड़िता की शिकायत पर यूनिट गंभीरता से कार्रवाई करेगी। पीड़िता को यूनिट के जरिए एक ही छत के नीचे अपराध नियंत्रण, अनुसंधान के साथ कानूनी सलाह भी मिलेगी। इससे उसे अलग-अलग जगह भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। हर यूनिट पर आधा खर्चा केन्द्र देगा और आधा खर्च राज्य वहन करेगा।

(रा.प., 13.09.15)

संगठन हमारी जान है! मिलकर हम तूफान हैं!!

पर्यावरण

प्रदेश में मरुस्थलीकरण रोकने के प्रयासों की जरूरत

राजस्थान में मरुस्थलीकरण, भूमिक्षरण तथा सूखे से बचाव के लिए सामुदायिक स्तर पर समन्वित प्रयास करने होंगे। इस तरह के पेड़-पौधे लगाने होंगे जो मिट्टी के कटाव को रोक सकें। इसके साथ पर्यावरण व जैव विविधता के संरक्षण के लिए ग्राम पंचायत स्तर तक सभी लोगों को जागरूक करना होगा।

यह विचार राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड के चेयरमैन प्रमोद कुमार ने 'कट्स' द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से 18 अगस्त को जयपुर में आयोजित 'मरुस्थलीकरण, भूमिक्षरण तथा सूखे से बचाव' विषयक राज्य स्तरीय कार्यशाला में व्यक्त किए।

कार्यक्रम में 'कट्स' निदेशक जॉर्ज चेरियन ने बताया कि राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश है इसलिए यहां ज्यादा काम करने की जरूरत है। देश में भौगोलिक क्षेत्र का 25 फीसदी भाग रेगिस्तान हो चुका है और 32 फीसदी भूमि की गुणवत्ता घटी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 'कट्स' व मंत्रालय के सहयोग से 295 स्वयंसेवी संस्थाएं अपने-अपने क्षेत्र में लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाएंगी और विभिन्न गतिविधियां संचालित करेंगी।

जन स्वास्थ्य

मिलेगा कैश लैस स्वास्थ्य बीमा

प्रदेश में एक करोड़ परिवारों को दिसम्बर से कैश लैस स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र और तमिलनाडू के बाद राजस्थान ऐसा तीसरा राज्य बन गया है, जहां सरकार स्वास्थ्य बीमा देगी।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के जरिए करीब चार करोड़ लोगों को निजी अस्पतालों में बिना प्रीमियम दिए तीन लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिल सकेगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अतिरिक्त मिशन निदेशक नीरज के पवन और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

राजे ने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी गुणवत्ता वाले निजी चिकित्सा संस्थान बड़ी संख्या में खुलने की संभावना है। *(दै.भा. एवं दै.न., 04.09.15)*

सड़क सुरक्षा

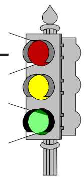

हेलमेट बोझ नहीं, सुरक्षा के लिए है!

ट्रैफिक नियम तोड़ना युवाओं के लिए स्टाइल सिंबल बन गया है। लोग हेलमेट रखते हैं लेकिन लगाते नहीं। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना और वाट्स-अप चैक करना युवाओं की आदत हो गई है। यह कहना है परिवहन सचिव एवं आयुक्त गायत्री राठौड़ का। यह बात उन्होंने आकाशवाणी पर लोगों से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर रोक के लिए रूबरू होते हुए कही।

उन्होंने बताया कि राजस्थान में प्रतिदिन 28 लोगों की मौत दुर्घटनाओं में हो रही है। पिछले साल राजस्थान में 10 हजार 280 लोगों की मौत हुई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान सड़क दुर्घटनाओं के मामले में पांचवें स्थान पर है।

सबसे अधिक दुर्घटनाएं नशे में वाहन चलाने, सीट बैल्ट नहीं लगाने, ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करने पर हो रही है। ओवरलोड वाहनों पर उठाए गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके लिए ऑपरेटर्स को पहल करनी चाहिए, वे वाहन में क्षमता से अधिक माल क्यों भरते हैं। उन्होंने बताया कि हम स्कूलों में रोड सेफ्टी का पाठ शामिल करने जा रहे हैं। *(दै.भा., 01.08.15)*

वित्तीय सेवाएं

बीमा क्षेत्र में खत्म होगी कमिशनखोरी

इंश्योरेंस रेग्यूलेटरी डवलपमेंट अथॉरिटी (इरडा) उस कमिशन में कमी करना चाहता है, जिससे शुरूआती प्रीमियम का बड़ा हिस्सा निकल जाता है और ग्राहक को इसकी जानकारी तक नहीं होती। पॉलिसी के पहले प्रीमियम पर अक्सर यह कमिशन 25-30 प्रतिशत तक होता है।

कमिशन को कम करने के लिए इरडा ने नए रूल्स बनाने का प्रस्ताव किया है। इसमें उन खर्चों की सीमा तय करने की बात है, जिन्हें इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम पर चार्ज कर सकती है। इससे डिस्ट्रीब्यूटर्स को दशकों पुराना भारी-भरकम कमिशन देने का कल्चर खत्म हो जाएगा, जिसके चलते पॉलिसी होल्डर्स को कम रिटर्न मिलता है।

इरडा इसी तरह अन्य कमिशन और खर्च की सीमा तय करने की दिशा में भी काम कर रहा है। इस बारे में एलआईसी के फॉर्मर चेयरमैन एस.बी.माथुर का कहना है कि नए रूल्स से पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राहकों को ज्यादा लाभ मिल सकेगा। *(दै.न., 24.07.15)*

दूरसंचार सेवाएं

ग्राम पंचायतें जुड़ेंगी ब्रॉडबैंड से

दूरसंचार विभाग देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ेगा। इसके लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। परियोजना को 'भारतनेट' का नाम दिया गया है।

यह जानकारी पंचायतीराज राज्य मंत्री निहालचंद ने संसद में ओम बिड़ला के सवाल के जवाब में देते हुए बताया कि 19 जुलाई 2015 तक 22 हजार 946 ग्राम पंचायतों में केबल बिछाने का काम पूरा हो चुका है। परियोजना को मार्च 2019 में पूरा किया जाना प्रस्तावित है। *(रा.प., 01.08.15)*

उपभोक्ता फैसले

घटिया बीज से फसल खराब, बीज कंपनी भरेगी नुकसान

जयपुर स्थित बस्सी के गांव अभयपुरा निवासी किसान सीताराम मीणा ने तुंगा रोड स्थित गीता खाद बीज भंडार से टमाटर के उन्नत बीज खरीदे। उन्होंने दुकानदार को कंपनी का कुबेर मार्का बीज और उसका उत्पाद नम्बर भी बताया। उन्होंने दुकानदार और बीज पर भरोसा रखकर खेत में बड़ी मेहनत कर फसल बोई, लेकिन जब फसल तैयार हुई तो पाया कि खेत में टमाटर काफी छोटे आए हैं। उन्हें बाजार तो क्या मंडी में भी नहीं बेचा जा सका।

भारी नुकसान होने पर उन्होंने इसकी शिकायत एसडीएम से की। उपनिदेशक कृषि विस्तार की जांच में भी टमाटर काफी छोटे और परजीवी के प्रकोप वाले पाए गए। सीताराम जागरूक किसान हैं। उन्होंने जिला उपभोक्ता मंच का दरवाजा खटखटाया। अपने परिवाद में उन्होंने मंच को पूरी जानकारी दी और साक्ष्य भी प्रस्तुत किए।

उपभोक्ता मंच ने बीज खराब होने से केवल किसान की फसल खराब होना ही नहीं, बल्कि इसे राष्ट्रीय उत्पादन को भी नुकसान होने का मामला करार दिया। मंच ने बीज उत्पादक हैदराबाद स्थित सिगनेट क्रॉप साइंसेज इंडिया प्राइवेट लि. कंपनी और दुकानदार गीता खाद बीज भंडार को आदेश दिए कि वह किसान सीताराम मीणा को एक लाख रुपए बतौर हर्जाने व पांच हजार रुपए परिवाद व्यय के अदा करें। *(रा.प., 13.08.15)*

गलत खून चढ़ाया, अब देना होगा 14.95 लाख हर्जाना

उत्तरप्रदेश में सहारनपुर के एक सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिला नीलम गुप्ता को डॉक्टर ए.के. मित्तल ने गलत खून चढ़ा दिया। नतीजा यह हुआ कि चार बार उसकी कोख से पैदा हुए बच्चों की मौत हो गई। मामला राज्य उपभोक्ता आयोग में दर्ज हुआ। राज्य आयोग ने डॉक्टर को दोषी मानते हुए पीड़िता नीलम गुप्ता को दो लाख रुपए का हर्जाना अदा करने का आदेश दिया।

डॉ.ए.के.मित्तल ने राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में अपील दर्ज कराई। सुनवाई पर आयोग ने अस्पताल, संबंधित ब्लड बैंक और डॉक्टर को दोषी माना। आयोग ने अपनी तीखी टिप्पणी में कहा कि ऐसे अनैतिक कामों और लापरवाही के कारण ही सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं लाचार होती जा रही हैं। सरकारी डॉक्टरों के लापरवाहिक रवैये की तरफ कोई जवाबदेही ही तय नहीं है। इससे गरीब मरीजों का शोषण होता है।

आयोग ने सरकारी अस्पताल में सामूहिक लापरवाही से हुई इस भयंकर गलती को दुर्लभ मामला मानते हुए आदेश दिया कि अस्पताल, संबंधित ब्लड बैंक और डॉक्टर ए.के. मित्तल मिलकर पीड़िता नीलम गुप्ता को 14 लाख 95 हजार रुपए का हर्जाना मय परिवाद खर्च के अदा करें। *(दै.भा., 17.07.15)*

खास समाचार

ई–कॉमर्स कंपनियां भी आएंगी उपभोक्ता अथॉरिटी के दायरे में

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पेश करते हुए बताया कि यह 1986 के उपभोक्ता संरक्षण कानून का स्थान लेगा। केबिनेट ने इस बिल को 28 जुलाई को मंजूरी दी थी। इसमें 1991, 1993 और 2002 में संशोधन भी हुए थे।

इस बार विधेयक में कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने का प्रावधान रखा गया है। नियामक का नाम सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी होगा। इसके पास प्रोडक्ट रिकॉल, रिफंड और मुआवजे का आदेश देने के अधिकार होंगे। आर्थोरिटी के पास भ्रामक प्रचार की जांच के साथ छानबीन और जब्ती का भी अधिकार होगा। यदि कोई कॉन्ट्रेक्ट उपभोक्ता हित के खिलाफ है तो यह उसे खारिज कर सकता है। अभी तक फूड सेफ्टी एजेंसी तभी कार्रवाई करती थी जब कोई शिकायत करे। अब इसे पॉवरफुल बनाया जा रहा है, वह अब कभी भी बिना शिकायत के खाद्य सामग्री के किसी भी मामले में जांच कर कार्रवाई कर सकेगी।

देश में बढ़ते ई–कामर्स कारोबार को दृष्टिगत रखते हुए उपभोक्ताओं के हित में ई-कॉमर्स कंपनियों को भी इसके दायरे में रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी मुकदमा दर्ज कराया जा सकेगा। कंपनी के खिलाफ क्लास एक्शन मुकदमा अर्थात सामूहिक रूप में मुकदमा दायर किया जा सकेगा। ऑनलाइन बिक्री करने वाले भी इसके दायरे में आएंगे। 'क्लास एक्शन' में सभी प्रभावित मुआवजे के हकदार होंगे। विधेयक में उपभोक्ता विवादों को जल्दी निपटाने के लिए मध्यस्थता का भी प्रावधान किया गया है। यह काम उपभोक्ता अदालतों की निगरानी में किया जाएगा। *(दै.भा., 30.07.15, 11.08.15)*

ग्राहक सुविधा केन्द्र

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है। आप उपभोक्ता सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी अथवा शिकायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

ग्राहक सुविधा केन्द्र
कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), डी–218 ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
ई–मेल: gsk@cuts.org फोन +091.141.4015395

स्त्रोत: रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति

पाँचवा–स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी–217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोन: 91.141.513 3259 फैक्स: 228 2485, टेलीफैक्स: 401 5395, ई–मेल: cart@cuts.org, वेबसाईट: www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।